IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नए प्रयोगों व परिवर्तनों से भारतीय शिक्षा विकास की ओर: नई शिक्षा नीति 2020

राजेश ओ.पी.सिंह

(Independent Scholar)

चंद्रिका आर्य

(Doctoral fellow, Department of Political Science, University of Delhi)

सारांश :-

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संपूर्णता व दिव्यदर्शन से भरपूर ऐसी शिक्षा नीति जिसमे सब कुछ समाहित हो, प्रत्येक देश के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है।

इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, जो कि डॉ. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बनी समिति द्वारा अनेकों विशेषज्ञों के सुझावों पर आधारित है। इस पेपर में हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लागू नई नीतियों के साथ साथ इसकी तुलना मौजूदा नीतियों के साथ करेंगे। इसके आलावा नई शिक्षा नीति द्वारा किए गए मुख्य परिवर्तनों और उनसे होने वाले फायदों का ज़िक्र भी करेंगे।

मुख्य शब्द:- नई शिक्षा नीति, फायदे, लागू करना, स्कूल, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता, नैतिकता, साक्षरता, परिवर्तन।

भूमिका :-

प्रत्येक देश में किसी भी मौजूदा नीति में सुधार या उसके स्थान पर नई नीति तभी लाई जाती है जब संभवतः मौजूदा नीति समकालीन समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती प्रतीत नहीं होती। इसी सिलसिले में भारत की केंद्र सरकार ने 34 वर्षों बाद 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया है।

ये माना जा रहा है कि 1986 की शिक्षा नीति से आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता , उत्पादकता और शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह और सुझाव लेते हुए कड़ी मेहनत और लबी जदोजहद के बाद नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया गया और इसे अथक प्रयासों से अमली जामा पहनाया गया है ।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी:-

भारत में मौजूदा शिक्षा नीति आधुनिक समय में तकनीक के साथ मेल जोल स्थापित नहीं कर पा रही थी और इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा के समय भी भारतीय छात्र व छात्राओं को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। विज्ञान और तकनीक के अभाव में कोरोना काल में भारतीय युवाओं को भारी नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ना तो बच्चों को और ना ही अध्यापकों को तकनीक के माध्यम से पढ़ाने का अनुभव था, इसलिए अचानक कोरोना आने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भारी ठेस लगी। हालांकि केंद्र सरकार पिछले 5 वर्षों से लगातार नई शिक्षा नीति पर कार्य कर रही थी और सरकार ने आगामी समय की ज़रूरतों को पूरा करने और अपनी दिव्यदर्शी सोच का प्रमाण देते हुए नए समय के लिए ये नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू की है।

इस शिक्षा नीति का एक ओर मुख्य लक्ष्य ये है कि साक्षर और शिक्षित के बीच की खाई को कम करके उसे भरा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछली सरकारों और विश्व बैंक जैसी अन्य विदेशी संस्थाओं के सहयोग से भारत ने साक्षरता दर में तो विकास किया है और ये आजकल 80 फीसदी से ऊपर है, परंतु शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है ,जिस से बेरोजगारी की समस्या पनप रही है। हम देखते है कि बच्चों के पास डिग्री तो है परन्तु उस डिग्री कोर्स में उन्होंने क्या विषय और पेपर पढ़े है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे साक्षर तो हो गए है परन्तु शिक्षित नहीं हो पाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, अब जब उन्हें अपने विषय जिसमे उन्होंने कोर्स पूरा किया है के बारे में आधारभूत सिद्धांतो, संकल्पनाओं और अवधारणाओं की जानकारी का अभाव है तो कैसे उन्हें उस डिग्री कोर्स की योग्यता पर नौकरी मिले? ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है क्योंकि बिना योग्यता के रोजगार कैसे मिलेगा। और ये केवल मानविकी कोर्सों में ही नहीं बल्कि वाणिज्य और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सों में भी है, इसलिए इस साक्षर व शिक्षित के बीच की खाई को भरने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी ।

पुरानी शिक्षा नीति में नैतिकता का भारी अभाव देखने को मिल रहा था, उस से अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के पार्टी कोई लगाव नहीं पनपता था, और इसी वजह से जिन मां बाप ने अपने बच्चे को अपनी कड़ी मेहनत के पैसों से पढ़ाया लिखाया वहीं बच्चे बड़े होकर उनसे अलग हो जाते है , उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल तक नहीं करते है। इसके साथ साथ भारत का सबसे तेज़ दिमाग विदेशों की तरफ आकर्षित है और एक बार जाने के बाद फिर कभी अपने देश को नहीं लौटता, जहां की भूमि ने उसे बड़ा किया, वहां से उसका लगाव छूट जाता है। ऐसे अनेक प्रमाण देखने की मिल रहे है जिनसे मौजूदा पीढ़ी में नैतिकता और देशप्रेम की भारी कमी देखने को मिलती है, इसलिए इस शिक्षा नीति में इस कमी को पूरा करने के प्रयास से कई आयामों को जोड़ा गया है ताकि आगामी पीढ़ी योग्यता सहित नैतिक और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके और भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके।

नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु:-

1. शिक्षण व सीखने का मिश्रित तरीका;

उच्चतर शिक्षा संस्थान ने विज्ञान व तकनीक के महत्व को समझते हुए सबसे बड़ा परिवर्तन किया है कि प्रत्येक कोर्स का 40 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा जिसे बच्चा जब चाहे जिस स्थान पर बैठ कर पढ़ सकेगा और बाकी का 60 फीसदी हिस्सा ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी आपदा में शिक्षा का नुकसान सबसे कम होएगा।

2. लचीलापन;

बहुस्तरीय प्रवेश और निकास (एग्जिट) अर्थात यदि कोई बच्चा किसी कारण से अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाता तो वो किसी भी स्तर पर उसे छोड़ सकता है और फिर कभी भी वापिस प्रवेश कर सकता है। ऐसे में यदि बच्चा एक वर्ष पूरा करके कोर्स छोड़ता है तो उसे प्रमाणपत्र दिया जाएगा, यदि दो वर्ष पूरे किए तो एडवांस डिप्लोमा ,यदि तीन वर्ष पूरे किए तो डिग्री और यदि चारों वर्ष पूरे कर लिए तो शोध सहित डिग्री प्राप्त करेगा। इससे बच्चे का समय बचेगा क्यूंकि उसे फिर से पहले वर्ष में नहीं जाना पड़ेगा। जहां से वो छोड़ेगा वहीं फिर से प्रवेश कर लेएगा।

इसके साथ साथ "एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" बनाया गया है जिसमें प्रत्येक पेपर के कुछ क्रेडिट मिलेंगे और वो बच्चे के इसी खाते में जुड़ जाएंगे और प्रत्येक स्तर के कोर्स के लिए कुछ क्रेडिटों की संख्या निर्धारित की गई है ,जब किसी बच्चे के पास उतने क्रेडिट हो गए, जितने किसी डिग्री के लिए आवश्यक थे तक उसे वो डिग्री प्रदान कर दी जाएगी।

3. विषयों का विभाजन;

इस बार सीबीएसई ने कक्षा 10 में गणित विषय को दो भागों में बांटा है, एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। अब ये बच्चे पर निर्भर करेगा कि वो किसका चयन करना चाहता है।

इसके साथ साथ बच्चा एक पेपर सोशल साइंस का पढ़ सकता है वहीं दूसरा पेपर किसी भाषा का या किसी विज्ञान के विषय का पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति में कौन से पेपर पढ़ने है ये बच्चे पर निर्भर करेगा , वो अपनी मनपसंद के पेपर पढ़ पाएगा। इस योजना से उत्पादकता और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होएगी क्यूंकि हर बच्चा अपनी पसंद के विषय में ज्यादा अव्वल आता है अब उसके पास विकल्प ही विकल्प है इसलिए वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को योग्य बना पाएगा।

4. परख का निर्माण किया गया है, (परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट) जो कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड बॉडी के रूप में कार्य करेगा। इस से सभी स्तरों की बोर्ड परीक्षाओं में सुधार आएगा।

5. उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को खत्म करके एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा, जिसे "हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया" (HECI) का नाम दिया गया है। उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों को देख रेख अब ये एकल नियामक निकाय ही करेगा।

इससे भ्रष्टाचार में कमी आने के संकेत है, और इसके साथ साथ बच्चों के सारे कार्य एक ही स्थान पर है जय करेंगे जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होएगी।

6. मातृ भाषा का प्रावधान करना अपने आप में एक बड़ी सफलता है क्योंकि कोई भी बच्चा सबसे पहले अपनी मातृ भाषा ही सीखता ओर समझना शुरू करता है, परंतु जब वो शिक्षा के लिए स्कूल में जाना शुरू होता है तो वह और भाषा होती है जिसे समझने में कई बार उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत से बच्चे इसीलिए आगे पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि भाषा उनके लिए रुकावट का कार्य करती है और उन्हें आधारभूत ज्ञान से वंचित करती है। अब जब मातृ भाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है तो इस से आगामी पीढ़ी को फायदा पहुंचेगा, क्यूंकि वो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में पढ़ेगा और लिखेगा, इस से ज्यादा उत्पादकता और गुणवत्ता आएगी।

इसके साथ साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी क्षत्रिय भाषाओं में पढ़ाई के ई-साधन उपलब्ध करवाने की बात कही है, अर्थात अब बच्चे सारा पाठ्यक्रम मातृ भाषा में इंटरनेट, टीवी, या अन्य माध्यमों पर पढ़ सकेंगे।

7. कॉलेज स्तर की कक्षा में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की गई है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे प्रत्येक बच्चे को कॉलेज में प्रवेश लेने का समान अवसर प्रदान

होएगा।

8. विश्व की 100 टॉप विश्वविद्यालयों को भारत में और भारत के टॉप 100 विश्वविद्यालयों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान की है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होएगा की जो कोई बच्चा विश्व की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है परन्तु उसके पास उस देश में जाने और रहने के पैसे नहीं नहीं तो वो अब भारत में ही उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस से पढ़ाई कर सकेगा। इससे लाखों युवाओं के सपने साकार होएंगे जो किन्हीं कारणों से विदेश जा पाने में असमर्थ थे।

लागू करने में कठिनाई:-

जैसा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में बोलते हुए "बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर" ने कहा था कि ' कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हुए, और कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो ,वो अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है ,यदि उस लागू करने वाले अच्छे हों ' अर्थात किसी भी नीति का अच्छा बुरा होना उसे लागू करने वालों पर निर्भर करता है, यदि लागू करने वाले अच्छे होएंगे और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होएगी और यदि लागू करने वाले लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से असफलता ही प्राप्त होएगी।

इसलिए सबसे आवश्यक है कि इसे लागू करने वाले पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लागू करे और जहां जो विवाद या असमझ या गड़बड़ हो उसे सही तरीके से तुरंत निपटाया जाए।

निष्कर्ष :-

हमने देखा कि अनेक देश अपनी परम्पराओं व संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी शिक्षा नीति में सुधार या बदलाव करते है साथ ही कई बार पूरी शिक्षा नीति को ही बदल दिया जाता है, इसी प्रकार भारत ने भी मौजूदा आधुनिक समय के साथ चलने के लिए भारतवासियों को नई शिक्षा नीति 2020 प्रदान की है। जिसमे अनेकों सुधारो के साथ साथ कुछ कमियां भी हो सकती हैं परंतु इस सबके बावजूद ये शिक्षा नीति भारतीयों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेगी। इस नई शिक्षा नीति में तकनीक के साथ जो गठजोड़ किया है वो आगामी पीढ़ी के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होएगा। और आज तक शिक्षा के अधिकार में बच्चों को उम्र 6 से 14 वर्ष थी जो अब नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष के दी है ,इसके सकारात्मक परिणाम लंबे समय तक भारत को मजबूती प्रदान करेंगे और विकास की तरफ अग्रसर रखेंगे।

अंत में हम कह सकते है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और विकास लाएगी।

संदर्भ:-

1.Ministry of Human Resources Development, Draft National Education Policy 2019(summary).

2. Ministry of Human Resources Development, National Education Policy 2020.

3. Press Information Bureau.

4. British council,UK. India's New Education Policy 2020: highlights and opportunities.

5. New Education Policy: Advantages and Disadvantages. Dr. Roshani Singh, Times of India, May 25th,2021.

6. Impact of New Education Policy 2020 on higher education. Ajay Kumar & Sudeep B. Chandranana. ResearchGate.

7. Theoretical extension of NEP 2020 using Twitter Mining. Rahul P. Singh, Sumit Narula & et.al. Vol.17,7, June2021.ISSN-2395-7514,JCCC.

8. नई शिक्षा नीति से बच्चों की स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक क्या क्या बदलेगा, नवभारत टाइम्स, 30 जुलाई,2020.